भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 301
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की प्रति व्यक्ति आय

***301. श्री आनंद भदौरियाः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2023 और 2024 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

किसानों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ श्री आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 301 के भाग (क) से (ग) का उललिखित विवरण

(क) से (ग): देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित "कृषि परिवारों की स्थिति आकलन का सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से समय-समय पर अनुमान लगाया जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77 वें चरण के सर्वेक्षण (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है । चूंकि कृषि परिवारों की आय के संबंध में पिछला सर्वेक्षण 2019 में किया गया था, इसलिए वर्ष 2023 और 2024 के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय की मात्रा उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, इसने किसानों की आय में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम), एग्री फंड फॉर स्टार्ट-अप एंड रुरल इंटरप्राइजेज (एग्रीश्योर), एकीकृत कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम ईनाम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), आदि शामिल हैं।

इन पहलों से पिछले पांच वर्षों में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय का अद्यतन डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना करना संभव नहीं है।

******